

TOPPERSEXAM.COM

18-07-2026



CURRENT AFFAIRS

HIGHLIGHTS

- INTERNATIONAL NEWS
- NATIONAL AFFAIRS
- BANKING NEWS
- AWARDS NEWS
- DEFENCE NEWS
- SPORTS NEWS
- SCI-TECH NEWS



7891099005, 7891099006





TODAY NEWS HIGHLIGHT

- मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS): भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण महाशक्ति बनाने की नई पहल
- विंडफॉल टैक्स (SAED) में संशोधन: ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात संतुलन की दिशा में सरकार का कदम
- कोलकाता मेट्रो में ड्राइवर रहित (GoA-4) ट्रेन संचालन: भारत के स्मार्ट शहरी परिवहन की नई दिशा
- सेमीकॉन 2.0: भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की नई राष्ट्रीय पहल
- राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026): उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में नया कदम
- उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी निर्माण: भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूत करने की नई पहल
- भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC): रणनीतिक साझेदारी को नई गति
- अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस (18 जुलाई): शांति, समानता और मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक संकल्प



1. मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS): भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण महाशक्ति बनाने की नई पहल

मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS) को 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य मोबाइल फोन एवं प्रमुख घटकों के स्वदेशी निर्माण, मूल्यवर्धन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत योग्य बिक्री, घरेलू सोर्सिंग और नवाचार पर प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यह योजना PLI योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



2. विंडफॉल टैक्स (SAED) में संशोधन: ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात संतुलन की दिशा में सरकार का कदम

भारत सरकार ने 16 जुलाई 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) / विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। इसके तहत डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाया गया है; हालांकि घरेलू पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के दौरान निर्यातकों के असाधारण लाभ को नियंत्रित करना तथा घरेलू ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।



3. कोलकाता मेट्रो में ड्राइवर रहित (GoA-4) ट्रेन संचालन: भारत के स्मार्ट शहरी परिवहन की नई दिशा

कोलकाता मेट्रो को ग्रीन लाइन पर GoA-4 (ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन-4) आधारित ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त हुई है। यात्री सेवाएं शुरू होने के बाद कोलकाता, दिल्ली और बंगलुरु के साथ पूर्णतः स्वचालित मेट्रो सेवा वाले भारत के चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा। यह प्रणाली Communication-Based Train Control (CBTC) तकनीक पर आधारित है, जिसमें ट्रेन बिना चालक के स्वचालित रूप से संचालित होती है। उन्नत सिग्नलिंग, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, स्वचालित ब्रेकिंग और रियल-टाइम निगरानी जैसी तकनीकों से मेट्रो संचालन अधिक सुरक्षित, कुशल और ऊर्जा-दक्ष बनेगा।



4. सेमीकॉन 2.0: भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की नई राष्ट्रीय पहल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को ₹1,27,500 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह योजना चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन (Fab), ATMP/OSAT, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास (R&D), कौशल विकास तथा संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास करना है। यह पहल AI, 5G, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, चिकित्सा उपकरण और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की तकनीकी एवं आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ करेगी।





5. राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026): उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में नया कदम

कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दी है, जो NIP-2012 का स्थान लेकर गैस-आधारित आधुनिक यूरिया संयंत्रों में निवेश को बढ़ावा देगी। इस नीति का उद्देश्य घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना तथा आत्मनिर्भर भारत और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें लागत संरचना को अधिक पारदर्शी बनाया गया है तथा निवेशकों के लिए 12% से 16% तक इक्विटी पर प्रतिफल (RoE) का प्रावधान किया गया है। इससे उर्वरक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध होगा और कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को बल मिलेगा।



6. उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी निर्माण : भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूत करने की नई पहल

भारी उद्योग मंत्रालय ने 10 GWh क्षमता की ACC (Advanced Chemistry Cell) बैटरी निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वैश्विक निविदाएँ जारी की हैं, जो ₹18,100 करोड़ की PLI योजना का अंतिम चरण है। ACC बैटरियाँ उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी आयु और तेज़ चार्जिंग वाली आधुनिक बैटरियाँ हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना तथा स्वच्छ ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। यह पहल मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



7. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC): रणनीतिक साझेदारी को नई गति

ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की तीसरी बैठक में AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। Trade and Technology Council (TTC) भारत और EU के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने वाला उच्च-स्तरीय रणनीतिक मंच है। बैठक में उन्नत प्रौद्योगिकी, हरित हाइड्रोजन, बैटरी तकनीक, ऊर्जा दक्षता और सतत गतिशीलता जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। यह सहयोग भारत की तकनीकी क्षमता, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।



8. अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस (18 जुलाई): शांति, समानता और मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक संकल्प

अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की जयंती पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2009 में इस दिवस की घोषणा की थी और इसका पहला आयोजन 18 जुलाई 2010 को हुआ। यह दिवस मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और शांति के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। मंडेला के 67 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को 67 मिनट समाज सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।





1. मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS) के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

A - ₹50,000 करोड़

B - ₹75,000 करोड़

C - ₹62,500 करोड़

D - ₹1,27,500 करोड़

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2026 को ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दी, जिसे 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी मोबाइल निर्माण, मूल्यवर्धन, R&D और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाना है।



2. संशोधित विंडफॉल टैक्स के तहत किस उत्पाद के निर्यात पर शुल्क घटाया गया है ?

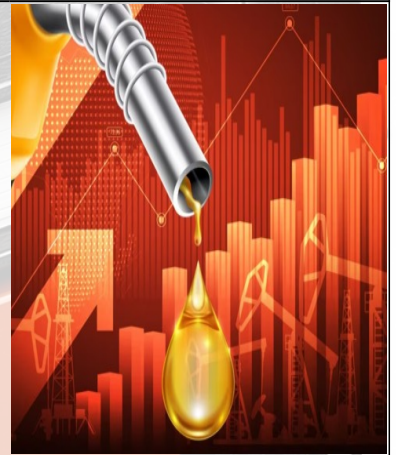
A - डीजल

B - एटीएफ (ATF)

C - पेट्रोल

D - एलपीजी

भारत सरकार ने 16 जुलाई 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED)/विंडफॉल टैक्स में संशोधन करते हुए डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया तथा पेट्रोल पर शुल्क घटाया है। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के दौरान अत्यधिक लाभ को नियंत्रित करना, घरेलू ईंधन उपलब्धता बनाए रखना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।



3. कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस लाइन पर शुरू की जाएगी ?

A - ब्लू लाइन

B - रेड लाइन

C - ग्रीन लाइन

D - येलो लाइन

कोलकाता मेट्रो को ग्रीन लाइन पर GoA-4 आधारित ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) से स्वीकृति मिल गई है। CBTC तकनीक पर आधारित यह प्रणाली मेट्रो संचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल, ऊर्जा-दक्ष और पूर्णतः स्वचालित बनाएगी।



4. सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है ?

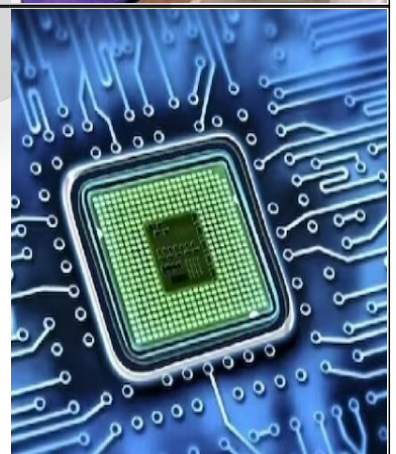
A - ₹62,500 करोड़

B - ₹75,000 करोड़

C - ₹1,27,500 करोड़

D - ₹1,50,000 करोड़

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह योजना चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, ATMP/OSAT, R&D और कौशल विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत तथा उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों को सशक्त करेगी।





5. राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को किस संस्था ने मंजूरी दी है ?

A - नीति आयोग

B - केन्द्रीय मंत्रिमंडल

C - कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA)

D - भारतीय रिजर्व बैंक

कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गैस-आधारित आधुनिक यूरिया संयंत्रों में निवेश बढ़ाकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह नीति आयात पर निर्भरता कम करने, किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर भारत और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।



6. ACC बैटरी निर्माण योजना किस क्षमता की इकाइयों की स्थापना से संबंधित है ?

A - 5 GWh

B - 8 GWh

C - 10 GWh

D - 20 GWh

भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹18,100 करोड़ की PLI योजना के अंतिम चरण के तहत 10 GWh क्षमता की ACC (Advanced Chemistry Cell) बैटरी निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वैश्विक निविदाएँ जारी की हैं। इसका उद्देश्य घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना तथा इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।



7. भारत-EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई ?

A - पेरिस

B - बर्लिन

C - ब्रुसेल्स

D - रोम

ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की तीसरी बैठक में AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह सहयोग भारत की तकनीकी क्षमता, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा।



8. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की घोषणा किस वर्ष की थी ?

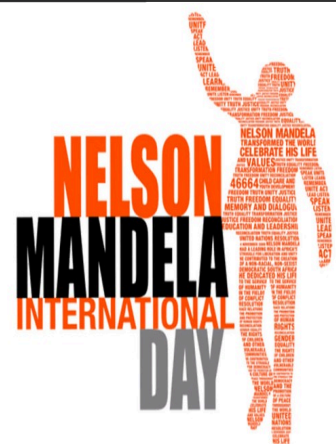
A - 2007

B - 2008

C - 2009

D - 2010

अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2009 में इसकी घोषणा की थी तथा मंडेला के 67 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को 67 मिनट समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है।





One Liner

1. कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन (GoA) पर आधारित है ? - **GoA-4 (ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन-4)** ।
2. राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) किस पुरानी नीति का स्थान लेगी ? - **राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (NIP)-2012** ।
3. 16 जुलाई 2026 से संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ? - **विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)** ।
4. ₹62,500 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS) किस अवधि के लिए लागू की जाएगी ? - **वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक** ।
5. ₹18,100 करोड़ की PLI योजना के अंतिम चरण में जारी वैश्विक निविदाएँ किस प्रकार की बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित है ? - **ACC (Advanced Chemistry Cell) बैटरी निर्माण इकाइयाँ** ।
6. अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ? - **18 जुलाई**
7. नेल्सन मंडेला के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को कितने मिनट समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है ? - **67 मिनट** ।
8. सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ? - **भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना** ।
9. भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के लिए स्थापित उच्च-स्तरीय मंच का नाम क्या है ? - **Trade and Technology Council (TTC)** ।
10. ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन में प्रयुक्त CBTC का पूर्ण रूप क्या है ? - **Communication-Based Train Control** ।

TOPPERSEXAM.COM

18-07-2026



CURRENT AFFAIRS

HIGHLIGHTS

- INTERNATIONAL NEWS
- NATIONAL AFFAIRS
- BANKING NEWS
- AWARDS NEWS
- DEFENCE NEWS
- SPORTS NEWS
- SCI-TECH NEWS



7891099005, 7891099006





TODAY NEWS HIGHLIGHT

- **Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS):** A new initiative to make India a global mobile manufacturing powerhouse
- **Amendment to Windfall Tax (SAED):** Government's move towards energy security and export balance
- **Driverless (GoA-4) Train Operations in Kolkata Metro:** A New Direction for Smart Urban Transportation in India
- **SEMICON 2.0:** A new national initiative to make India a global semiconductor superpower
- **National Urea Investment Policy-2026 (NIPU-2026):** A new step towards self-reliance in the fertilizer sector
- **Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Manufacturing:** A New Initiative to Strengthen India's Energy Storage Capability
- **India-EU Trade and Technology Council (TTC):** New momentum for strategic partnership
- **International Nelson Mandela Day (18 July):** A global commitment to peace, equality and human rights



1. Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS): New initiative to make India a global mobile manufacturing superpower

The Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) was approved by the Union Cabinet on 15 July 2026 with a budget of ₹62,500 crore, to be implemented from the financial year 2026-27 to 2030-31. Its objective is to encourage indigenous manufacturing, value addition, research and development (R&D) of mobile phones and key components and Indian brands. Under the scheme, performance-based financial incentives will be provided on eligible sales, domestic sourcing and innovation. This scheme is an important step towards making India a global mobile manufacturing and export hub by taking forward the success of PLI scheme.



2. Revision in Windfall Tax (SAED): Government's Move Towards Energy Security and Export Balance

The Government of India has revised the Special Additional Excise Duty (SAED)—also known as windfall tax—on the export of petroleum products, effective July 16, 2026. Under this revision, the duty on the export of diesel and ATF (Aviation Turbine Fuel) has been increased, while the duty on petrol exports has been reduced; however, there has been no change in the excise duty on domestic petrol and diesel. The objective of the windfall tax is to curb the extraordinary profits earned by exporters during periods of rising global oil prices and to ensure domestic fuel supplies.



3. Driverless (GoA-4) Train Operations on Kolkata Metro: A New Direction for India's Smart Urban Transport

Kolkata Metro has received safety clearance from the Commissioner of Railway Safety (CRS) for GoA-4 (Grade of Automation-4) based driverless metro operations on the Green Line. Once passenger services commence, Kolkata will join the select group of Indian cities—alongside Delhi and Bengaluru—to offer fully automated metro services. This system is based on Communication-Based Train Control (CBTC) technology, where the train operates automatically without a driver. Technologies such as advanced signaling, platform screen doors, automatic braking, and real-time monitoring will make metro operations safer, more efficient, and energy-efficient.



4. Semicon 2.0: A New National Initiative to Make India a Global Semiconductor Powerhouse

The Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 program with a budget of ₹1,27,500 crore, aiming to transform India into a global semiconductor manufacturing hub. The scheme focuses on strengthening the entire semiconductor ecosystem, including chip design, fabrication (Fab), ATMP/OSAT, packaging, R&D, and skill development. Its objective is to reduce import dependency and foster an indigenous semiconductor industry under the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative. This initiative will bolster India's technological and economic capabilities in strategic sectors such as AI, 5G, electric vehicles, defense, medical devices, and industrial electronics.





5. National Investment Policy for Urea-2026 (NIPU-2026): A New Step Towards Self-Reliance in the Fertilizer Sector

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the National Investment Policy for Urea-2026 (NIPU-2026), which will replace NIP-2012 and boost investment in modern, gas-based urea plants. The policy aims to reduce dependence on imports by increasing domestic urea production and strengthening 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) and food security. It introduces a more transparent cost structure and provides for a Return on Equity (RoE) ranging from 12% to 16% for investors. This move is expected to increase investment in the fertilizer sector, ensure timely urea availability for farmers, and bolster the long-term sustainability of the agricultural sector.



6. Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Manufacturing: A New Initiative to Strengthen India's Energy Storage Capacity

The Ministry of Heavy Industries has issued global tenders for setting up ACC (Advanced Chemistry Cell) battery manufacturing units with a capacity of 10 GWh; this marks the final phase of the ₹18,100 crore PLI scheme. ACC batteries are modern batteries characterized by high energy density, long lifespan, and fast charging capabilities, finding applications in electric vehicles, energy storage, and renewable energy projects. The scheme aims to reduce import dependence by boosting domestic battery manufacturing and strengthening the clean energy and electric vehicle ecosystem.



7. India-EU Trade and Technology Council (TTC): New Momentum for Strategic Partnership

At the third meeting of the India-EU Trade and Technology Council (TTC) held in Brussels, an agreement was reached to enhance cooperation in areas such as AI, semiconductors, electric vehicles, renewable energy, digital technology, and secure supply chains. The TTC is a high-level strategic forum designed to foster trade, technology, investment, and digital innovation between India and the EU. The meeting placed special emphasis on sectors including advanced technology, green hydrogen, battery technology, energy efficiency, and sustainable mobility. This collaboration will strengthen India's technological capabilities, investment, clean energy initiatives, global supply chain integration, and the goal of an 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India).



8. International Nelson Mandela Day (July 18): A Global Commitment to Peace, Equality, and Human Rights

International Nelson Mandela Day is observed annually on July 18, marking the birth anniversary of Nelson Mandela, the former President of South Africa and a Nobel Peace Prize laureate. The United Nations General Assembly (UNGA) declared this day in 2009, and it was first observed on July 18, 2010. The day aims to raise awareness and inspire people regarding human rights, equality, democracy, social justice, and peace. In honor of Mandela's 67 years of public service, people are encouraged to dedicate 67 minutes to community service.





1. What amount has been approved for the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)?

A - ₹50,000 crore

B - ₹75,000 crore

C - ₹62,500 crore

D - ₹1,27,500 crore

The Union Cabinet approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) worth ₹62,500 crore on July 15, 2026, to be implemented from 2026-27 to 2030-31. Its objective is to transform India into a global hub for mobile manufacturing and exports by promoting indigenous mobile manufacturing, value addition, R&D, and Indian brands.



2. Under the revised windfall tax, the duty on the export of which product has been reduced?

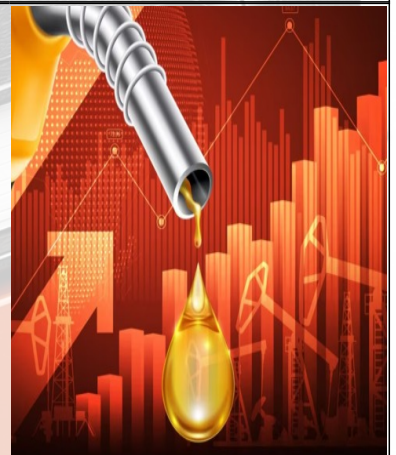
A - Diesel

B - ATF

C - Petrol

D - LPG

The Government of India revised the Special Additional Excise Duty (SAED)/windfall tax on the export of petroleum products effective July 16, 2026; duties on diesel and ATF were increased, while the duty on petrol was reduced. The objective is to curb excessive profits during the rise in global oil prices, maintain domestic fuel availability, and strengthen energy security.



3. On which line will the Kolkata Metro's driverless service be launched?

A - Blue Line

B - Red Line

C - Green Line

D - Yellow Line

Kolkata Metro has received approval from the Commissioner of Railway Safety (CRS) for GoA-4 based driverless metro operations on the Green Line. Based on CBTC technology, this system will make metro operations safer, more efficient, energy-efficient, and fully automated.



4. What budget has been approved for the Semicon 2.0 program?

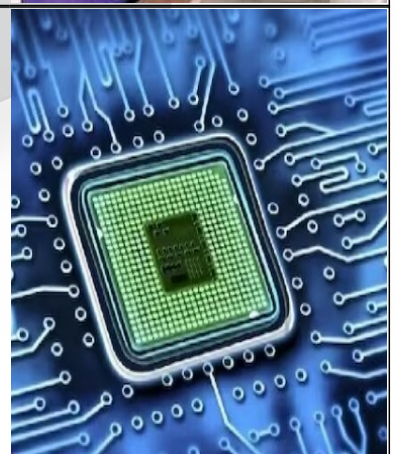
A - ₹62,500 crore

B - ₹75,000 crore

C - ₹1,27,500 crore

D - ₹1,50,000 crore

The Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 program with a budget of ₹1,27,500 crore, aiming to make India a global semiconductor manufacturing hub. This scheme will empower 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) and high-technology industries by fostering chip design, fabrication, ATMP/OSAT, R&D, and skill development.





5. Which body has approved the National Urea Investment Policy-2026 (NIPU-2026)?

A - NITI Aayog

B - Union Cabinet

C - Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)

D - Reserve Bank of India

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the National Urea Investment Policy-2026 (NIPU-2026), which aims to boost domestic production by increasing investment in modern gas-based urea plants. This policy will reduce dependence on imports, ensure timely availability of urea to farmers, and strengthen 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) and food security.



6. The ACC battery manufacturing scheme relates to the establishment of units with what capacity?

A - 5 GWh

B - 8 GWh

C - 10 GWh

D - 20 GWh

The Ministry of Heavy Industries has issued global tenders for setting up ACC (Advanced Chemistry Cell) battery manufacturing units with a capacity of 10 GWh under the final phase of the ₹18,100 crore PLI scheme. Its objective is to reduce import dependence by boosting domestic battery manufacturing and to strengthen the electric vehicle, energy storage, and green energy ecosystems.



7. Where was the third meeting of the India-EU Trade and Technology Council (TTC) held?

A - Paris

B - Berlin

C - Brussels

D - Rome

At the third meeting of the India-European Union (EU) Trade and Technology Council (TTC) held in Brussels, an agreement was reached to enhance cooperation in sectors such as AI, semiconductors, electric vehicles, renewable energy, and secure supply chains. This collaboration will strengthen India's technological capabilities, investments, clean energy, digital innovation, and the goal of a self-reliant India (Atmanirbhar Bharat).



8. In which year did the United Nations General Assembly (UNGA) declare International Nelson Mandela Day?

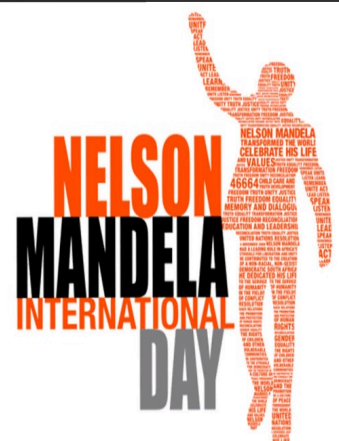
A - 2007

B - 2008

C - 2009

D - 2010

International Nelson Mandela Day is observed annually on July 18—Nelson Mandela's birthday—to promote the values of human rights, equality, democracy, and peace. The United Nations General Assembly (UNGA) declared this observance in 2009, and people are encouraged to dedicate 67 minutes to community service in honor of Mandela's 67 years of public service.





One Liner

1. On which date is International Nelson Mandela Day observed annually? - **July 18.**
2. What is the primary objective of the Semicon 2.0 program? - **To make India a global semiconductor manufacturing hub.**
3. Which earlier policy will the National Urea Investment Policy-2026 (NIPU-2026) replace? - **National Urea Investment Policy (NIP)-2012.**
4. On which Grade of Automation (GoA) is the Kolkata Metro's driverless service based? - **GoA-4 (Grade of Automation-4).**
5. For how many minutes are people encouraged to engage in community service in honor of Nelson Mandela's public life? - **67 minutes.**
6. By what name is the revised Special Additional Excise Duty (SAED), effective from July 16, 2026, commonly known? - **Windfall Tax.**
7. The global tenders issued in the final phase of the ₹18,100 crore PLI scheme relate to which type of battery manufacturing units? - **ACC (Advanced Chemistry Cell) battery manufacturing units.**
8. For which period will the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS), approved with a budget of ₹62,500 crore, be implemented? - **From the financial year 2026-27 to 2030-31.**
9. What is the name of the high-level forum established between India and the European Union (EU) for trade, technology, and digital cooperation? - **Trade and Technology Council (TTC).**
10. What is the full form of CBTC, used in driverless metro operations? - **Communication-Based Train Control.**